नईदुनिया

संक्षिप्त समाचार

सेंसेक्स 650 अंक उछला, कच्चे तेल में गिरावट और वैश्विक संकेतों से बाजार में तेजी

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान जोरदार तेजी देखने को मिली। दोपहर करीब 11:45 बजे तक बीएसई का सेंसेक्स 668 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78,224 पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई का निफ्टी 198 अंक या 0.85 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,225 पर पहुंच गया। बाजार में केवल लार्जकैप शेयरों में ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी का रुख देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 721 अंक यानी 1.28 प्रतिशत चढ़कर 56,892 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 274 अंक यानी 1.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 16,406 पर कारोबार करता नजर आया। विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में तेजी की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। सोमवार को यह कीमत 119 डॉलर प्रति बैरल तक चली गई थी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में संकेत दिया था कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध समाप्त होने के करीब है, जिससे तेल बाजार में नरमी आई। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती ने भी निवेशकों के भरोसे को बढ़ाया है। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया मजबूत बना रहा और इसका उच्चतम स्तर 91.72 तथा न्यूनतम स्तर 92.33 प्रति डॉलर दर्ज किया गया। वहीं बाजार में उतार-चढ़ाव को दर्शाने वाला इंडेक्स इंडिया विक्स भी गिरावट के साथ 19.77 पर आ गया, जो करीब 15.37 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। इसे भी बाजार में स्थिरता और तेजी का संकेत माना जा रहा है। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी घरेलू बाजार के सेंटीमेंट को मजबूत किया। एशिया के सोल, हांगकांग, शंघाई, टोक्यो, बैंकॉक और जकार्ता के बाजार बढ़त के साथ खुले, जबकि अमेरिकी बाजार भी सोमवार को हरे निशान में बंद हुए थे।

एप्पल ने भारत में आईफोन उत्पादन 53 प्रतिशत बढ़ाया

नई दिल्ली। दिग्गज अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने 2025 में भारत में उत्पादन करीब 53 प्रतिशत बढ़ाया है और इस दौरान करीब 5.5 करोड़ यूनिट्स की असेंबली की है, यह आंकड़ा इससे पहले के वर्ष में 3.6 करोड़ यूनिट्स था। यह जानकारी रिपोर्ट्स में दी गई। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि एप्पल अमेरिका में चीनी उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ से बचने के लिए भारत में अपने करीब एक चौथाई फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि एप्पल वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 22-23 करोड़ आईफोन का उत्पादन करता है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह सरकार द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) के तहत मिलने वाला प्रोत्साहन है। पीएलआई के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन ने चीन की तुलना में कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाओं और रसद संबंधी चुनौतियों जैसी संरचनात्मक लागत संबंधी कमियों को दूर करने में मदद की है।

एनएसई का ब्रोकर्स को निर्देश अतिरिक्त एसटीटी लौटाएं

मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने मंगलवार को ब्रोकर्स से वित्त वर्ष 2023-24 और उससे पहले सालों में एकत्रित किए गए अतिरिक्त सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी), जो कि सरकार को जमा नहीं किया गया है, को लौटाने और खुलासा करने को कहा है। एनएसई ने यह कदम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निर्देश मिलने के बाद उठाया है। सर्कुलर में एनएसई ने कहा कि यह कदम आयकर के संयुक्त आयुक्त, रेंज 7(1) से संदेश मिलने के बाद उठाया गया है, जिसमें यह बताया गया था कि कुछ ब्रोकरों ने आवश्यक राशि से अधिक एसटीटी एकत्र किया था और इसे सरकारी खाते में जमा करने के बजाय अपने पास रखा था। एनएसई सर्कुलर में ब्रोकरों और उप-ब्रोकरों को 31 मार्च, 2023 तक एकत्रित और जमा न किए गए अतिरिक्त एसटीटी का विवरण सीधे एक्सचेंज को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा कि ब्रोकरों को अतिरिक्त एसटीटी सर्कुलर प्रकाशित होने के सात दिनों के भीतर एक्सचेंज के पास जमा करनी होगी। एसटीटी, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री पर लगने वाला टैक्स है। एक्सचेंज ने कहा कि ब्रोकरों को अतिरिक्त एसटीटी और देरी के प्रत्येक महीने पर 1

चावल नरम; गेहूं मजबूत; दालों, खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव

नयी दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में मंगलवार को चावल के औसत भाव टूट गये। वहीं, गेहूं में तेजी रही। चीनी के भाव कमोबेश स्थिर रहे जबकि दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत नौ रुपये घटकर 3,847 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी। गेहूं तीन रुपये महंगा हुआ और 2,813 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आटे के भाव में टिकाव रहा। दाल-दलहनों में तुअर दाल औसतन 32 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई। मसूर दाल की कीमत 22 रुपये और चना दाल की 20 रुपये घट गयी। मूंग दाल में नौ रुपये की गिरावट रही। वहीं, उड़द दाल दो रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुई। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का मई वायदा 139 रिंगिट फिसलकर 4,428 रिंगिट प्रति टन रह गया। मई का अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.12 प्रतिशत की बढ़त में 66.18 सेंट प्रति पौंड बोला गया। स्थानीय बाजारों में सूरजमुखी तेल 73 रुपये और पाम ऑयल 63 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ। मूंगफली तेल की कीमत 39 रुपये बढ़ी। सरसों तेल और सोया तेल आठ-आठ रुपये मजबूत हुए।

ऐतिहासिक निचले स्तर से उबरा रुपया, 36 पैसे मजबूत

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया मंगलवार को 36 पैसे मजबूत हुआ और ऐतिहासिक निचले स्तर से उबरकर कारोबार की समाप्ति पर 91.85 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 39 पैसे टूटकर 92.21 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। रुपये में आज शुरू से ही तेजी रही। यह 28.50 पैसे की मजबूती के साथ 91.9250 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। बीच कारोबार में इसमें काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। यह ऊपर 91.7150 रुपये और नीचे 92.1925 रुपये प्रति डॉलर तक गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में नरमी से रुपये को समर्थन मिला।

रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, प्राकृतिक खेती और बढ़ते निर्यात से मजबूत हो रही कृषि अर्थव्यवस्था

दुनिया की खाद्य जरूरतें पूरी करने की दिशा में बढ़ रहा भारतः शिवराज

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की कई योजनाओं को राज्य सरकार सही तरीके से लागू नहीं कर रही है, जिसके कारण वहां के गरीब किसान इन महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि देश में इस समय रिकॉर्ड स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है और भारत की कृषि क्षमता की दुनिया भर में सराहना हो रही है। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग 357 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय दोनों मजबूत हुई हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत ने करीब 150 मिलियन टन से अधिक चावल उत्पादन के साथ दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है और इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा गेहूं, सरसों, सोयाबीन और मूंगफली जैसी प्रमुख फसलों में भी रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब भारत को पीएल-480 योजना के तहत आयातित गेहूं पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज देश के गोदाम गेहूं और चावल से भरे हुए हैं। स्थिति यह है कि सरकार को अनाज के भंडारण की चिंता करनी पड़ रही है, जबकि दुनिया भारत के किसानों और कृषि नीतियों की सराहना कर रही है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने दालों, फलों और सब्जियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि दालों का उत्पादन करीब 19 मिलियन टन से बढ़कर 25-26 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है।

इसी तरह बागवानी उत्पादन भी 369

मिलियन टन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है, जो किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक बड़ा स्रोत बन रहा है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। इसके तहत गंगा जैसी नदियों के किनारों पर बड़े क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश भर में एक करोड़ से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया गया है और लाखों हेक्टेयर भूमि पर क्लस्टर बनाकर इस पद्धति को अपनाया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि अगर प्राकृतिक खेती सही तरीके से की जाए तो उत्पादन कम नहीं होता, बल्कि कई मामलों में पहले से ज्यादा बढ़ जाता है।

उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में किसानों को प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे महंगे रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जगह स्थानीय संसाधनों पर आधारित पारंपरिक भारतीय पद्धतियां अपना सकें। इस मॉडल में देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से बने घनजीवामृत, बीजामृत और नीमास्त्र जैसे जैविक घोलों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इंटरक्रॉपिंग के जरिए एक ही खेत में अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर रहती है और किसानों की लागत भी कम होती है। कृषि मंत्री ने कहा कि आज भारत का खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति के शुरुआती दौर की तुलना में कई गुना बढ़ चुका है और अब इसकी वृद्धि दर भी पहले से तेज हो गई है। उन्होंने बताया कि 2014-15 के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 40 से 42 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दलहन, तिलहन, बागवानी और दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिससे किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा दोनों को मजबूती मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट लक्ष्य है कि भारत केवल अपने नागरिकों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने तक सीमित न रहे, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया की खाद्य जरूरतों को भी पूरा करने वाला देश बने। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन, बेहतर भंडारण क्षमता और बढ़ती निर्यात संभावनाओं के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। आने वाले समय में भारत की यह भूमिका और भी मजबूत होगी।

केंद्र ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के लिए 3,630 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मंगलवार को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 3,630.77 करोड़ रुपए की संशोधित कुल लागत को मंजूरी दे दी। यह परियोजना दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-सोहना स्पर से जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत उत्तर प्रदेश और हरियाणा में विकसित की जाएगी।

करीब 31.42 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स की दक्षता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यह कॉरिडोर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) से भी जुड़ेगा, जिससे सड़क, माल ढुलाई और अन्य परिवहन साधनों के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित होगी।

सरकार के अनुसार, यह एलिवेटेड कॉरिडोर केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं है, बल्कि शहरी विकास, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एक कैबिनेट नोट में कहा गया है कि फरीदाबाद क्षेत्र में टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करने और जेवर एयरपोर्ट-दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए इस परियोजना का निर्माण जरूरी है।

सरकारी बयान के मुताबिक, इस परियोजना के करीब 11 किलोमीटर हिस्से को एलिवेटेड हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। यह हिस्सा डीएनडी-बल्लभगढ़ बाईपास और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी का अहम भाग होगा और इसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।

यह कॉरिडोर फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031 के तहत चिन्हित उस क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जहां भविष्य में घनी आबादी वाला शहरी विकास और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की योजना है।

इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की अतिरिक्त लागत 689.24 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से हरियाणा सरकार 450 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। इसके अलावा, पिछले महीने सरकार ने गुजरात में नेशनल हाईवे-56 के दो हिस्सों को चार लेन में अपग्रेड करने की परियोजना को भी मंजूरी दी थी, जिसकी कुल लागत 4,583.64 करोड़ रुपए है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने कहा कि इस योजना के तहत धमासिया-बिटाडा/मोवी (47.46 किमी) और नासरपोर-मलोथा (60.21 किमी) सेक्शन को चार लेन में विकसित किया जाएगा। इन दोनों हिस्सों की कुल लंबाई 107.67 किलोमीटर होगी। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से देश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेड से बढ़ेगी रफ्तार और क्षमता, 'कवच' सुरक्षा प्रणाली को मिलेगा बल

रेलवे में तकनीकी सुधार के लिए 765 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली । भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक को मजबूत करने के लिए सरकार ने 765 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे संचालन को बेहतर बनाना, लाइन क्षमता बढ़ाना और नेटवर्क के महत्वपूर्ण हिस्सों में आधुनिक संचार प्रणाली विकसित करना है। रेल मंत्रालय के अनुसार, इन परियोजनाओं में दो व्यस्त माल और यात्री कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड करना और वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा और मुंबई सेंट्रल डिवीजनों में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क का विस्तार शामिल है। सरकार ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के 106 किलोमीटर लंबे दुव्वाडा-विशाखापत्तनम-विजयनगरम सेक्शन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 318.07 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस सेक्शन को मौजूदा 1M25 केवी सिस्टम से आधुनिक 2.25 केवी सिस्टम में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे इस व्यस्त कॉरिडोर पर माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों की रफ्तार में सुधार होगा और संचालन अधिक भरोसेमंद बनेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना रेलवे बजट 2024-25 में शामिल उस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरे भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को आधुनिक बनाना है।

इसके अलावा, सरकार ने साउथ सेंट्रल रेलवे के गुंटकल डिवीजन के तहत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित 126 किलोमीटर लंबे रायचूर गुंटकल सेक्शन में भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 259.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

इस योजना के तहत करीब 1,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी, जिसमें वडोदरा डिवीजन में 692 किलोमीटर और मुंबई डिवीजन में 308 किलोमीटर शामिल हैं।

चंडीगढ़ ब्रांच फॉड मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 645 करोड़ रुपए के दावे चुकाए

नई दिल्ली। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मंगलवार को बताया कि उसने अपनी चंडीगढ़ शाखा में हुए धोखाधड़ी मामले से जुड़े दावों के रूप में 645 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। यह राशि बैंक के शुरुआती अनुमान से लगभग 55 करोड़ रुपए ज्यादा है। बैंक ने यह भी कहा कि जांच के दौरान अब तक कोई नई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि पहले 590 करोड़ रुपए की मूल राशि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बाद में मिले दावों के आधार पर कुल 645 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। बैंक के अनुसार, यह सभी दावे उसी घटना और उसी चंडीगढ़ शाखा से जुड़े हैं; कोई नया मामला सामने नहीं आया है। बैंक ने यह भी बताया कि सभी संबंधित खातों का मिलान पूरा कर लिया गया है और 25 फरवरी 2026 के बाद से देश भर में कोई नया दावा नहीं मिला है। बैंक ने कहा कि उसने अपने सिद्धांतों के अनुसार प्रभावित ग्राहकों को यह भुगतान किया है और आगे भी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा ताकि नुकसान की राशि की वसूली की जा सके। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बताया कि इस घटना के बावजूद बैंक की जमा राशि (डिपॉजिट बेस) स्थिर बनी हुई है। 28 फरवरी तक बैंक का कुल डिपॉजिट 2,92,381 करोड़ रुपए था, जबकि दिसंबर के अंत में यह 2,91,133 करोड़ रुपए था। बैंक ने अपने ग्राहकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सिर्फ चंडीगढ़ की एक शाखा से जुड़ी अलग घटना है। बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (एलसीआर) भी मौजूदा तिमाही में 114 प्रतिशत के आरामदायक स्तर पर है। बैंक को उम्मीद है कि भविष्य में भी डिपॉजिट और लोन की वृद्धि पहले की तरह जारी रहेगी।

भारत का सालाना खाद्य निर्यात पॉच लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा: गोयल

नई दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को खाद्य, कृषि और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े लोगों से भारत को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (प्रोसेस्ड फूड) का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते व्यापार समझौते और भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग इस दिशा में बड़े अवसर पैदा कर रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित आहार - द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर के 40वें संस्करण के उद्घाटन के दौरान गोयल ने कहा कि भारत का खाद्य और कृषि उत्पादों का निर्यात, जिसमें कृषि उत्पाद और मत्स्य पालन शामिल हैं, अब सालाना करीब 5 लाख करोड़ रुपए (55 अरब डॉलर से अधिक) तक पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक बन गया है।

उन्होंने बताया कि 2014 से 2025 के बीच पिछले 11 वर्षों में भारत के कृषि और खाद्य निर्यात में काफी तेजी आई है। इस दौरान प्रोसेस्ड फूड का निर्यात चार गुना, फल और दालों का

निर्यात तीन गुना, प्रोसेस्ड सब्जियों का निर्यात चार गुना, कोको का निर्यात तीन गुना और अनाज का निर्यात दोगुना हो गया है। वहीं चावल का निर्यात भी इस अवधि में 62 प्रतिशत बढ़ा है।

गोयल ने कहा कि ये उपलब्धियां भारत को कृषि और प्रोसेस्ड फूड निर्यात में दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य पूरी तरह हासिल किया जा सकता है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के अनुरूप है, जिसमें भारत को दुनिया की फूड बास्केट बनाने की बात कही गई है। मंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारत ने नौ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं, जिनसे 38 विकसित और समृद्ध देशों के बाजारों तक पहुंच मिली है। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए बड़े अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत को वैश्विक व्यापार के लगभग दो-तिहाई हिस्से तक प्राथमिक बाजार पहुंच प्राप्त है, जिससे भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन रहा है और भारतीय कंपनियां वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ रही हैं। गोयल ने कहा कि एफटीए वार्ता के दौरान सरकार ने घरेलू हितधारकों, खासकर किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के हितों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है।

फरवरी में म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लो 29,845 करोड़ रुपए रहा

मुंबई। मासिक एसआईपी इनफ्लो फरवरी में 29,845 करोड़ रुपए रहा है, जो कि जनवरी में 31,002 करोड़ रुपए था। यह जानकारी मंगलवार को जारी किए गए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के डेटा से मिली। हालांकि, सालाना आधार पर मासिक एसआईपी इनफ्लो में 15 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। फरवरी 2025 में यह 25,999 करोड़ रुपए था। नेट इक्विटी इनफ्लो फरवरी में बढ़कर 25,977.91 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि जनवरी में 24,028.59 करोड़ रुपए था।

फरवरी में मल्टीकैप फंड में 1,933.53 रुपए का नेट इक्विटी इनफ्लो दर्ज किया गया है, जो जनवरी में 1,995.23 करोड़ रुपए था। लार्ज कैप फंड में 2,111.68 करोड़ रुपए का नेट इक्विटी इनफ्लो आया है। यह जनवरी में 2,004.98 करोड़ रुपए था। यह आंकड़ा लार्ज एंड मिड कैप फंड के लिए जनवरी के 3,181.89 करोड़ रुपए से घटकर 3,137.73 करोड़ रुपए हो गया है। जनवरी में मिड कैप फंड में 4,002.99 करोड़ रुपए का नेट इक्विटी इनफ्लो आया, जो कि जनवरी में 3,185.47 करोड़ रुपए था। फरवरी में नेट इक्विटी इनफ्लो स्मॉलकैप फंड के लिए 3,881.06 करोड़ रुपए रहा, जो कि जनवरी में 2,942.11 करोड़ रुपए था।

फरवरी में सेक्टोरल/थीमैटिक फंड के लिए नेट इनफ्लो 2,987.29 करोड़ रुपए रहा है, जो कि जनवरी में 1,042.56 करोड़ रुपए था। फरवरी में सबसे अधिक इक्विटी इनफ्लो फ्लेक्सी कैप फंड में दर्ज किया गया है, जो कि 6,924.65 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि, जनवरी में यह 7,672.36 करोड़ रुपए था।

स्पेशल खबर कैबिनेट की मंजूरी, 'सुजलम भारत' डिजिटल फ्रेमवर्क से गांवों में जल आपूर्ति की होगी निगरानी

जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा, बजट 8.69 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और इसके स्वरूप में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इस मिशन का फोकस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक साफ पीने के पानी की सेवा को प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा।

सरकार ने इस योजना के पुनर्गठन के तहत कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार की सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपए होगी, जो पहले 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपए से काफी अधिक है। यानी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी में 1.51 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। योजना के तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क सुजलम भारत भी लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत हर गांव को एक यूनिक सुजल गांव या सर्विस एरिया आईडी दी जाएगी, जिसके माध्यम से पानी के स्रोत से लेकर घर तक की पूरी जल आपूर्ति प्रणाली को डिजिटल रूप से मैप किया जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को योजना के क्रियान्वयन और औपचारिक हस्तांतरण में शामिल किया जाएगा, जिसे जल अर्पण प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाएगा।

किसी भी ग्राम पंचायत को हर घर जल घोषित करने से पहले यह प्रमाणित करना होगा कि गांव में पानी की आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। सरकार का मानना है कि समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व इस योजना की सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से हर साल जल उत्सव आयोजित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें गांव के लोग मिलकर जल व्यवस्था की समीक्षा और रखरखाव करेंगे।

साल 2019 में इस योजना की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों (करीब 17 प्रतिशत) में ही नल से पानी की सुविधा थी। इसके बाद से अब तक 12.56 करोड़ से अधिक नए ग्रामीण घरों को नल का

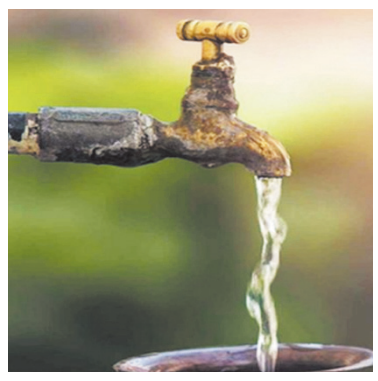

पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्तमान में देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से लगभग 15.80 करोड़ घरों (81.61 प्रतिशत) में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध हो चुका है। सरकार के अनुसार, जल जीवन मिशन का असर केवल पानी की उपलब्धता तक सीमित नहीं रहा है। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के आकलन में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, इस योजना की वजह से करीब 9 करोड़ महिलाओं को रोज पानी लाने की मेहनत से राहत मिली है, जिससे वे अब अन्य आर्थिक गतिविधियों में भाग ले पा रही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुमान के मुताबिक, इस योजना से महिलाओं के श्रम में रोजाना करीब 5.5 करोड़ घंटे की बचत हो रही है। साथ ही डायरिया से होने वाली करीब 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है और लगभग 1.4 करोड़ डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स (डीएएलवाई) की बचत संभव है।

नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रेमर के अनुसार, इस योजना से पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 30 प्रतिशत तक कमी आ सकती है, जिससे हर साल करीब 1.36 लाख बच्चों की जान बच सकती है। वहीं आईआईएम बेंगलुरु और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अध्ययन के अनुसार, इस मिशन से 59.9 लाख प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। सरकार के अनुसार, जेजेएम 2.0 के तहत दिसंबर 2028 तक देश के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराकर सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल प्रमाणित किया जाएगा। साथ ही, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समझौते किए जाएंगे, ताकि योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके और जल सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक प्रभावी बनाया जा सके। सरकार का कहना है कि जल जीवन मिशन 2.0 केवल बुनियादी ढांचे पर केंद्रित नहीं होगा, बल्कि इसे नागरिक-केंद्रित सेवा मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीसों घंटे सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर ग्रामीण जल आपूर्ति ढांचे के दीर्घकालिक संचालन, रखरखाव और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए समन्वित रणनीति पर भी काम करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति स्थायी और भरोसेमंद बन सके।